

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में आयोजनागत मद हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 938/बजट-08/खा0ग्रा0/06-07, दिनांक: 29 मई, 2006 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजना में ₹0 1,00,00,000/- (₹0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.03.2007 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक: 31.03.2007 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4- शासनादेश की शर्तों का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

5- यदि स्वीकृत धनराशि से कोई उपकरण/फर्नीचर अथवा कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामग्री आदि का क्रय किया जाता है तो क्रय किये जाने वाली सामग्री का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जाय अथवा टैण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6- कम्प्यूटर कय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तरांचल के दिशा-निर्देशों/ शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7- धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शासन/बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों व मानकों के अधीन किया जा रहा है।

8- स्वतः रोजगार योजनाओं हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित किया जाये एवं इसी के अनुरूप चयन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। लाभार्थियों के चयन के उपरान्त यथासम्भव एक माह के भीतर अनुदान की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। अनुदान के भुगतान में किसी भी दशा में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-आयोजनागत, 105-खादी ग्रामोद्योग, 03-खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजना-00, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 1945/XXVII(2)/2006, दिनांक: 01 दिसम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 3388(1)/VII-2/12-खादी/2006, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

62/11/06
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।